नदियों की स्वच्छता एवं प्रदूषण से मुक्ति का संकल्प

मध्यप्रदेश की नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना 'जल गंगा संवर्धन अभियान' का एक अभिन्न अंग है। इसके तहत, औद्योगिक इकाइयों और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे और दूषित पानी को नदियों में मिलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कई शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि गंदे पानी को साफ करके ही नदियों में छोड़ा जाए। उद्योगों को भी अपने अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करने के लिए निर्देशित किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नदी तटों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिससे नदियों का प्राकृतिक प्रवाह सुनिश्चित हो सके। लोगों को नदियों में कचरा न डालने और उन्हें स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह प्रयास न केवल नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। स्वच्छ नदियां प्रदेश की जीवनरेखा हैं और इन्हें प्रदूषण मुक्त रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।

सिंचाई और कृषि में जल दक्षता, किसानों को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार कृषि क्षेत्र में जल दक्षता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत, किसानों को खेत–तालाब बनाने और सिंचाई की आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे न केवल जल की बचत हो रही है, बल्कि फसल उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है।

प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए 50 हजार नए खेत–तालाब बनाने का लक्ष्य इस अभियान का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, नहरों की मरम्मत और जलाशयों से रिसाव को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह प्रयास किसानों को जल संकट से मुक्ति दिलाएगा।

nwda.gov.in